अभ्रक खान श्रमिक हितकारी कोष द्वारा राजस्थान में किया गया कार्य

8615. **श्री रूपलाल सोमानी :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक खान श्रमिक हितकारी कोष, राजस्थान द्वारा भीलवाड़ा जिले में गत तीन वर्षों से कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं और उस पर कितना व्यय हुआ तथा उससे कितने श्रमिकों को लाभ पहुंचा ;

(ख) उपरोक्त कार्यों के विस्तार के लिए क्या योजनायें विचाराधीन हैं और यदि इस संबंध में कोई योजना नहीं है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कार्यों के सफलतापूर्वक संचालन में परामर्श के लिए राज्य स्तर पर कोई सलाहकार समिति है और वह समिति कब से है और उसमें कब-कब परिवर्तन होते रहे हैं और यदि ऐसी कोई सलाहकार समिति नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क) भीलवाड़ा क्षेत्र में अभ्रक खान श्रमिकों के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं, मनोरंजन, शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, आर्थिक सहायता प्राप्त आवास आदि प्रदान करने के लिए बहुत सी योजनाओं को अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि से धन दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत खर्च की गई राशि और उस क्षेत्र में अभ्रक खान श्रमिकों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है।

(आंकड़े लाखों में)

	1976-77	1977-78	1978-79
	रुपये	रुपये	रुपये
1. स्वास्थ्य .	5.72	4.02	4.89
2. शिक्षा .	1.10	1.10	0.96
3. मनोरंजन .	1.64	1.89	2.01
4. आवास .	0.03	—	0.02
जोड़ .	8.49	7.01	7.88
श्रमिकों की संख्या .	1015	857	840

अधिकांश श्रमिकों और उनके आश्रितों को निधि द्वारा चलाई गई किसी न किसी योजना से लाभ हुआ है।

(ख) उक्त क्षेत्र में अभ्रक खदान परिचालन में कमी के कारण कल्याण कार्य-कलापों का बहुत बड़े आधार पर विस्तार करने की इस समय कोई परिकल्पना नहीं है।

(ग) जी हां। समिति का 1952 में पहली बार गठन किया गया था और तत्पश्चात् समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया। वर्तमान समिति 1973 में गठित की गई थी और 1976 में इसमें कुछ साधारण परिवर्तन किए गए।

दक्षिण पूर्व रेलवे के बारे में शाह आयोग से प्राप्त मामले

8616. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे नागपुर के ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है, जो विभागीय जांच के लिए मंत्रालय को शाह आयोग से प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनकी अभी जांच पड़ताल की जानी है;

(ग) इस बारे में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) किस निश्चित अवधि तक विभागीय जांच पूरी करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Deputation of S.A.S. Accountants to M/o External Affairs

8617. SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether S.A.S. Accountants were taken on deputation by his Ministry in 1978 as in previous years;

(b) whether contrary to the usual practice of keeping them on deputation here for three years, they have been ordered to report to their parents departments by the 31st May 1979;

(c) if so, the reason therefor;

(d) have these men been declared surplus; and

(e) in view of the unsettling position of such short term transfers and

the hardship caused to their families, will Government reconsider their decision and allow them to continue for their full term of three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU): (a) to (e). In 1978, as in previous years, the services of some SAS Accountants were taken by the Ministry of External Affairs on deputation as a sufficient number of accounts trained personnel were not available within the Ministry.

As in the past the deputation period was for a period of one year initially, renewable in case of requirement. As a sufficient number of accounts trained officers from the IFS 'B' are now becoming available it was decided that the deputation period of SAS Accountants should not be extended and that the posts should be filled as laid down in the IFS 'B', (R.C.S.P.) Rules, 1964. However on some of the SAS Accountants representing that they may be retained up till the end of May 1979 to coincide with the end of the academic session, this was agreed.

These officers have not been declared surplus but their services have been placed at the disposal of their parent departments on the expiry of the period for which these services were requisitioned.

New Railway Station Building

8618. SHRI G. BHUVARAHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state in view of Panrutti being the Municipal Town, Taluk Headquarters and big business centre, is there any proposal to construct a new railway station Building with modern amenities as the present one is very old and also inadequate to the present needs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): For the present there is no proposal to construct a new station building at Panrutti as the existing building though old is considered adequate to deal with the present level of traffic at this station.

Employment Opportunities for Rural Workers in Off-Season

8619. SHRI P. M. SAYEED:
SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY:
SHRI A. R. BADRINARAYAN:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Mathew Committee on National Employment Service has expressed the views that a full employment policy should aim at to create more opportunities for productive employment to rural workers during agriculture off-season when they are unemployed;

(b) whether Government also feel that farmers need work during off-season;

(c) whether the Union Ministry is considering any steps in this regard; and

(d) if so, the details of the proposed scheme being considered?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The recommendation has been forwarded to all the State Governments and Central Ministries for obtaining their views for enabling the Central Government to take a final decision. The matter will be finalised after we have received replies from the State Governments|Central Ministries.